>

Title: Need to curb the menace of black money in the country.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): देश में कितना कालाधन है तथा कितना देश से बाहर, इस आंकड़े पर मतभेद हो सकता है। पर यह कटु सत्य हे कि भारत में कालेधन का जाल आजादी के बाद जनसंख्या वृद्धि के समानुपात में बढ़ा है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 6 दशकों में देश की अर्थव्यवस्था को इससे करीब 25 हजार अरब रूपए का नुकसान हुआ है। पिछले दिनों वाशिंगटन के खोजी पत्रकारों के एक संगठन ने दुनिया भर के ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक किए जो अपने अपने देशों की अर्थव्यवस्था से छल कर रहे हैं। इस सूची में 600 से अधिक भारतीयों के नाम भी हैं जिनमें राजनीतिज्ञों के अलावा कुछ बड़े कारोबारी भी शामिल हैं। इस खबर से हर निष्ठावान भारतीय को सदमा पहूँचा है। अपने देश में लोकतंत्र है लेकिन इस लोकतंत्र की जननी निर्वाचन प्रक्रिया से ही कालेधन की कालिख फैलनी शुरू हो जाती है। अपने महान देश के अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए देश में भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ निर्णायक जंग आज की जरूरत है।

अतः सरकार से अनुरोध है कि वो भ्रष्ट राजनेताओं तथा अधिकारी वर्ग की संपत्ति का ऑडिट कराएं तथा जो बेनामी संपत्ति मिले उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए।